of the Electric Arc Furnace (Mini Steel Plants) units with the Designated Authority under the provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

महाराष्ट्र में भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों हेतु राहत कार्य

*366. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों के लिए राहत कार्य अब भी जारी है, यदि हां, तो उसका और राहत और पुनर्वास कार्यों में हुई प्रगति के बारे में लिए गए जायजे का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि राहत और पुनर्वास कार्य का जायजा लेने के लिए विश्व बैंक के दो सदस्यीय दल ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक वृहत पुनर्वास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना 27 जून, 1994 को शुरू हुई है और इसे 30 जून, 1997 तक पूरा कर लिया जाएगा।

इस परियोजना के अंतर्गत पुनः बसाए गए 52 गांवों में 25,000 मकानों का पुनर्निर्माण और 13 प्रभावित जिलों में 1.80 लाख क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम शुरू किया गया है। पुनः बसाए गए गांवों में 600 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 10,000 अन्य मकानों के निर्माण का कार्य चल रहा है। क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 1.14 लाख लाभानभोगियों को 35.00 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक विश्व बैंक पर्यवेक्षी मिशन ने 31 जनवरी से 9 फरवरी, 1995 के दौरान महाराष्ट्र का दौरा किया।

Discovery of Hindu Temples in China

*367. SHRI SOM PAL : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to a report in the 'Economic Times' dated 6 January, 1995, to the effect that some ancient Hindu temples have been found in China;

(b) if so, whether Government propose to have these studied by archaeologists in collaboration with the Chinese Government; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government proposes to obtain more precise information on the subject through Embassy and take suitable follow-up action.

(c) Does not arise.

Reserevation in KVS

*368. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2931 given in the Rajya Sabha on 31st March, 1995 and state :

(a) the details of the steps taken to implement the reservation policy in KVS;

(b) whether the Sangathan has issued any supplementary advertisement announcing the mode of extending the reflected reservation to the entitled candidates of OBCs in different States;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Kendriya Vidyalaya Sangathan follows the reservation policy of the Government.

(b) to (d). The main advertisement for teaching posts in Kendriya Vidyalaya Sangathan of 28th May, 1994 duly contains reservation for OBCs. The supplementary advertisement of 21st January, 1995 only clarified position about reservation for exservicemen and physically handicapped candidates.

Review Committee on Sardar Sarovar Project

*369. SHRI P. UPENDRA:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1910 given in the Rajya Sabha on 24th March, 1995 and state:

(a) the reasons for constituting a five members group to review all issues related to Sardar Sarovar Project in defiance of Narmada Tribunal Award; and

(b) the reasons for which the height was subjected to review as the Narmada Tribunal Award lays down that the height of the dam can be reviewed only after 2024 A. D.?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) The Constitution of Five Member Group to continue the discussions on various issues related to Sardar Sarovar Project was not in violation of the Narmada Water Disputes Tribunal Award. The Group was constituted to act as a sounding board or a listening post for the Government as discussions are considered to be important component of democratic process for getting representative views on various issues. The Group was set up by the Government with the hope that through series of discussions many of the misgivings about the project might be removed and that some useful suggestions about the Resettlement & Rehabilitation and environmental concerns might be received which would help in speedy implementation of the project.

(b) The height of Sardar Sarovar dam was not subjected to review by the Government. However, as per the directions of the Supreme Court of India during the hearing on the Writ Petition (Civil) No. 319/1994 in the matter of Narmada Bachao Andolan versus Union of India and others, this issue was referred to the Five Member Group for further Report.

हिन्दी/उर्दू विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य में हुई प्रगति

*370. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी और उर्दू विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अब तक क्या प्रगति हुई है; और इन्हें कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इनके लिए उचित स्थलों का चनाव एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सरकार ने वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधेयकों का प्रारूप तैयार करने के लिए दो विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं । विधायी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने